RAJYA SABHA

Wednesday, the 25th July, 1973/rAe *Srd Sravana,* 1895 *{Saka).*

The House met at eleven of the clock. MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

साक्षरता कार्यक्रम

*61. श्री जगदीश प्रसाद माथुर : †
डा० भाई महावीर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री कृष्ण कान्त :
डा० जैड० ए० अहमद :
श्री कोटा पुन्नैया :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :
श्री काली मुखर्जी :
श्री महेन्द्र कुमार मोहता :
श्री ए० जी० कुलकर्णी :
श्री चन्द्र शेखर :
श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :
श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :

क्या [शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में साक्षर लोगों का प्रतिशत कितना है और क्या निरक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या साक्षरता-प्रसार का कोई व्यापक कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

■fThe Question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Prasad Mathur.

LITERACY PROGRAMME

•61. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI YOGENDRA SHARMA :
SHRI KRISHAN KANT t
DR. Z. A. AHMAD :
SHRI KOTA PUNNAIAH :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI O. P. TYAGI :
SHRI KALI MUKHERJEE :
SHRI M. K. MOHTA :
SHRI A. G. KULKARNI :
SHRI CHANDRA SHEKHAR :
SHRI D. THENGARI :
SHRI N. K. SHEJWALKAR :
SHRI V. K. SAKHLECHA :

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE *be* pleased to state :

(a) the precentage of literates in the country at present; and whether the num ber of illiterate people is on the increase; and if so, the reasons therefor;

(b) whether any comprehensive programme regarding the spread of literacy is under Government's consideration; and

(c) if so, the details thereof?]

THE DEPUTY MINISTER IN THr MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) According to Census of India 1971 ("Paper I of 1971—Supplement—Provisional Population Totals) percentage of literates in the country is 29.34. Though the number of illiterates has increased from 333 million to 386 million between 1961 and 1971, the rate of illiteracy has gone down from 76% to 71% among per-

jff] English translation.

sons of all ages. Many factors appear to have contributed to the increase in the number of illiterates. The more important among these are : the large increase in population, inadequate enrolment of children of the age-group 6—14 in schools and the large number of drop-outs in primary education.

(b) and (c) The Central Advisory Board of Education which includes all State Education Ministers has formulated the strategy for eradication of illiteracy. The main features of which arc : —

(i) The provision of universal primary education in the age-group 6—14 by 1980-81, through intensified enrolment drive, multi-point entry, and part-time education;

(ii) Liquidation of illiteracy in the age-group 15—25 ;

(iii) Linking of literacy programmes with employment programmes; and

(iv) Development of literacy programmes amongst adults through voluntary services especially by college students.

†[**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत की वर्ष 1971 की जनगणना (1971 के पेपर 1—अनुपूरक जनगणना के अस्थायी आंकड़े) के अनुसार देश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता 29·34 है। यद्यपि निरक्षर व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1961 और 1971 के बीच 333 मिलियन से बढ़कर 386 मिलियन हो गई है परन्तु सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों की निरक्षरता की दर 76% से घटकर 71% हो गई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में हुई वृद्धि के लिए अनेक कारण जिम्मेदार है। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण कारण ये है: जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि स्कूलों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अपर्याप्त दाखिला और प्राथमिक शिक्षा को बहुत अधिक संख्या में छोड़ जाने वाले बच्चे।

(ख) और (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं, निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक नीति तयार की है जिसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) व्यापक दाखिला अभियान, बहुमुखी दाखिले तथा अंशकालिक शिक्षा के माध्यम से वर्ष 1980-81 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वग में देशव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।

(ii) 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त करना।

(iii) साक्षरता कार्यक्रमों को रोजगार-कार्यक्रमों से सम्बद्ध करना; और

(iv) प्रौढ़ों में स्वैच्छिक सेवाओं विशेषकर कालिज छात्रों के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रमों का विकास।]

[MR. CHAIRMAN in the Chair]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह आप ने जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में कारण दिये हैं उन के बारे में क्या सरकार ने इस बात की जानकारी की है कि बच्चों के स्कूल में दाखिल न होने का मुख्य कारण उन के माता पिता की आर्थिक स्थिति है और आज देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि सरकार प्रत्येक गांव में उस के लिये स्कूल भी नहीं खोल पा रही है और ऐसे कारण से

†[ ] Hindi translation.

जहां तक प्राइवेट क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, वहां स्कूलों में उन से शुल्क वसूल किया जाता है और जो संविधान में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उन की शिक्षा के लिए 10 वर्ष का समय निश्चित किया गया था कि इस समय के भीतर ही उन के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी, लेकिन उस के बाद बहुत लम्बा समय बीत गया है। तो इस दृष्टि से क्या सरकार उन कारणों की जांच करेगी कि जिन की वजह से यह नहीं हो सका और कोई समय निश्चित करेगी जिस में वह इस प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और कंपल्सरी करने की दृष्टि से कोई व्यवस्था करने को तैयार हो?

श्री डी० पी० यादव : जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है उस में एक बात में मैं उन से सहमत हूं कि गरीबी के कारण भी हम लोगों को प्राथमिक शिक्षा पर आघात पहुंचा है, लेकिन हमारे प्रयास कम रहे हैं यह मैं मानने को बहुत अधिक दूर तक तैयार नहीं हूं। हमारा प्रयास जो पंचवर्षीय योजना में है वह यह है कि 1980-81 तक 14 साल तक के बच्चों को कम से कम 75 परसेंट बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ले आयें और 11 साल तक के बच्चों को निश्चित रूप से हम प्राथमिक शिक्षा के दायरे में ले आयेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रौढ़ों के संबंध में जो शिक्षा की आप ने व्यवस्था की है उसमें केवल कालेज छात्रों के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रमों के विकास की व्यवस्था है, लेकिन उसी संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से जो शैक्षणिक संस्थायें हैं उन पर काफी रुपया व्यय होता है। तो कितना रुपया इस में अब तक उन पर व्यय किया गया है और कितने प्रौढ़ शिक्षित हुए और प्राथमिक रूप से सरकार अगर इस प्रौढ़ शिक्षा को जो पिछड़ी जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन के गांवों तक सीमित रखती तो शायद अधिक लाभ हो सकता था, तो क्या इस सारे पैसे को उधर डाइवर्ट करने की सरकार की कोई योजना है?

श्री० डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सारे देश की है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के गांवों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार और प्रचार करें इस के लिए हम तैयार हैं और हमेशा हम उस की मदद करेंगे, लेकिन जहां तक एलोकेशन का संबंध है, शिक्षा तो राज्य सरकार का विषय है। हम लोग तो इनपुट्स और इंसेंटिव देने की स्थिति में हैं और उस में करीब करीब चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था।

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, जो आंकड़े बयान में प्रस्तुत किये गये हैं वे बड़े ही दुखद और भयावह हैं क्योंकि यह आंकड़े बतलाते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है सिवाय चीन के, जिस की कुल जनसंख्या हमारे यहां की अशिक्षित लोगों की जो संख्या है उस से अधिक हो। दुनिया के सभी देश चीन के सिवाय, ऐसे हैं कि जिन की जनसंख्या हमारे देश की अशिक्षित जनसंख्या से कम है...

श्री सभापति : आप ने कह दिया, अब सवाल करिये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हमारे देश में अशिक्षितों की संख्या...

श्री सभापति : अब यह आप तीसरी बार कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : दुनिया के तमाम देशों से अधिक है और इस के लिए जो उपाय यहां बताये गये हैं क्या ये काफी हैं और क्या लिट्रेसी प्रोग्राम के विकास के बारे में वालंटियरी सर्विस की जो बात कही गयी है, क्या सरकार सोचती है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिस में थोड़े से कंपल्शन की भी एलीमेंट हो जैसे कि कालेज के विद्यार्थी हैं उन के लिए इस लिट्रेसी कार्यक्रम में दो या तीन साल काम करना अनिवार्य बना दिया जाय। क्या सरकार का ऐसा विचार है ?

श्री सभापति : ठीक है, शर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल है, अब जवाब देने दीजिये।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, माननीय शर्मा जी का सुझाव मंत्रालय को स्वीकार्य है और मंत्रालय उस दिशा में कार्य करेगा।

SHRI KRISHAN KANT ; Sir, I would like to know whether the reply given by the Minister does not itself show some discrepancy from the figures given by the Census Commissioner and supplied to Members of Parliament. It showed 29.46 per cent in 1971 whereas the Minister's it gives the figure of 29.34 per cent. Which is correct? ' I do not know whether the Ministry has really consulted them or they have their own figures. Now, if we see th; table, in 1951 the percentage of literate population was 16.67. Now in 1971. it is 29.46 per cent, that is, less than 1." per cent increase in a period of 20 years. Is it not a matter of shame *toTjbis* country, when we have been plamnhg for about 25 years, that there has been only half a per cent increase in literacy every year? May I know what the basic reason is . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : शिक्षा मंत्रालय को कैबिनेट स्तर का भी नहीं बनाया गया है।

SHRI KRISHAN KANT : Please, let me finish. I think whether it is the Minister of State or the Cabinet Minister, they have full authority to guide the destiny of education in India and they quite capable of doing it. Let him not divert me from the issue. Now, is this not a iv state of affairs that there has been only | per cent increase in literacy every year during the lust 20 years? May I know whether the Government is i conscious of what they have done and whether they think the planning can ;d with the expected participation e! the people when there is so much illiteracy in this country? In China . . .

MR. CHAIRMAN : Mr. Krishan Kant, I cannot allow too many questions and I cannot allow this elaboration.

SHRI KRISHAN KANT : Sir, I am asking a simple thing. One of the Ministers in the Chinese Government said that they in China are trying to follow Gandhiji's method of basic education, productive education. May I know what the Government has done in this country l i make education productive so that people do not feel it necessary to take away their children to agriculture and industry instead of sending them to school?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी श्री कृष्ण कान्त जी ने जो यह कहा है कि हमारे यहां लिट्रेसी में वृद्धि .5 परसेंट हुई है यह तो फिगर का विषय है, उसको हम मानते हैं।

AN HON. MEMBER : He is not audible.

SHRI D. P. YADAV : As I said, this is figure work and we accept it. So far as our efforts towards vocationalisation is concerned particular emphasis is given in the teaching of Centra! Schools, I can assure the hon. Member that in the Central Schools at least, which are directly under our control, we have now decided to orient the courses in such a way that they will be vocational in nature.

DR. Z. A. AHMAD : I do not think can ask any new question. Only I want

sonic information about the expenditure on thf promotion of primary education: 1 would like to know from the hon. Minister whether any calculation has been made as to the percentage of the amount spent promotion of primary education, per-*t* the total expenditure in the last three or four flan-. If so, what is that tage?

SHRI D. P. YADAV : Sir, in the State and Central sectors, including Plan and non-Plan expenditure, our total yearly outlay is approximately Rs. 1,000 crores on education on the whole. I cannot give him the exact figure now because it is not available with me. However, I will supply it later. On primary education, it will not be less than 70 per cent, approximately, oi the total expenditure on education.

DR. Z. A. AHMAD : I want the percentage of the total Plan expenditure.

SHRI D. P. YADAV : I will supply it

SHRI KOTA PUNNAIAH : May I know which is more, the rate of increase in population or the rate of increase in idly, I would like to know the percentage of literacy among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI D. P. YADAV : The answer to part (a) of the question of the hon. Member is that it is population. So far as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned, definitely we have lagged hi hind. But 1 have repeatedly assured the House thai we are making every endeavour and every effort so that we can give a good lead to it.

, SHRI KOTA PUNNAIAH: Sir, would he supply the percentage at a later date?

SHRI D. P. YADAV : Yes, Sir. I will supply it.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञान है कि प्रान्तीय सरकारें अभी तक अपने प्रान्तों में सभी ीण क्षेत्र में स्कूलों की स्थापना करने में असमर्थ रही हैं और जो अगला भारत आ रहा है वह साक्षर हो सकेगा, इसमें संदेह है। तो क्या सरकार प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाकर अपने हाथ में लेकर 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बनान का विचार करेगी ?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अभी प्राइमरी स्कूलों की संख्या करीब-क़रीब 5 लाख है। गांवों की भी संख्या 5 लाख के आसपास है। कहीं कहीं एनामली हो सकती है लेकिन हमने यह कोशिश किया है कि हर 300 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल रहे, और जहां नहीं है उसके वास्ते पिछले सत्र 1971-72 में तीस हजार, 1972-73 में हमने 30,000 शिक्षकों की बहाली की और 1973-74 में हम क़रीब-क़रीब 1 लाख शिक्षकों को इस शिक्षा के प्रसार के लिए बहाल करने जा रहे हैं और हमारे मंत्रालय को यह आशा है कि हम इसमें अच्छा कार्य कर सकेंगे।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न . . .

श्री सभापति : उनका सवाल इसको सेन्ट्रल सब्जेक्ट बनाने के बारे में था। उसका जवाब दे दीजिए।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, यह विषय कांट्रोवर्शियल है और अभी हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे।

SHRI D. THENGARI : While some reasons are given for our lagging behind in this respect, may I know whether the Government is aware that one of the main reasons for our lagging behind is the pitiable plight of our primary school teachers regarding their pay scales ami service conditions? Will the Government assure that the Central Government would protect their pay scales and service conditions?

May I know whether the Government is e that while various agencies are campaign, there is no proper coordination amongst them? Is the Government thinking of constituting any central coordinating agency for this put pose?

SHRI i). P. YADAV : Sir, I am reply-last part of his question. We ■ got a Central Board here consisting of tiie State Ministers as well as the Central Ministers. And regularly we sit together. an exchange of views. We i out a plan and take a decision there. Till this being a State subject, we cannot interfere too much in their sphere.

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मंत्री जी ने केन्द्र से सम्बन्धित जो विद्यालय हैं उनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में प्राइमरी स्कूल नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि ग्वालियर में जो सेन्ट्रल स्कूल है उसमें भी क्लास पांच तक लोगों के बच्चों को भर्ती नहीं मिल पाती है। वहां पर आर्मी के और दूसरे सेन्ट्रल कर्मचारियों के बच्चें हैं जिन्हें उस स्कूल में भर्ती नहीं मिल पाती है। गांवों की बात तो छोड दीजिये, वहां पर तो प्राइमरी स्कूलों की कमी है ही, लेकिन आज तो शहरों में भी बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस बारे में क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ सालों से देश के विभिन्न भागों में जो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है उनमें शिक्षण का कार्य एवरेज स्कूलों से बढ़िया है और यही कारण है कि वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाती है। इन स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को लिया जाता है और जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर होते हैं, उनके बच्चों को लिया जाता है। इसके बावजूद भी जिन कक्षाओं में जगह बच जाती है उनमें बाहर के बच्चों को लिया जाता है। हमारे पास इस सम्बन्ध में फाइनेंस की कठिनाई है जिसकी वजह से हम इन स्कूलों का ज्यादा विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में पत्र लिखें और मैं उस स्कूल के बारे में देखूंगा।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मैंने बाहर के लोगों के बारे में नहीं कहा बल्कि जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे हैं उनके बारे में कहा था जिनको इन स्कूलों में जगह नहीं मिलती है। वहां पर ए० जी० का दफ्तर है और आर्मी का हैडक्वार्टर भी है। आप ने कहा कि बाहर के लोगों के बच्चों को भी लिया जाता है, यह बात तो ठीक है, लेकिन ग्वालियर में आर्मी का हैडक्वार्टर होने के कारण तथा दूसरे सरकारी दतपर होने के कारण क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेंगे जिससे इन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल में जगह मिल सके?

श्री० डी० पी० यादव : जैसा मैंने अभी कहा कि आप इस बारे में लिख दें और मैं इस चीज को देखूंगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त करना और साक्षरता कार्यक्रमों को रोजगार कार्यक्रमों से सम्बद्ध करना है। तो रोजगार के कार्यक्रमों को सम्बद्ध करने के लिए जो कुछ क्राफ्ट्स की शिक्षा चल रही है उससे अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके...

या नहीं? अगर नहीं हो सकेगा, तो क्या शिक्षा प्रणाली में सरकार परिवर्तन करने की बात सोच रही है? जिस तरह से सरकार ने यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन बनाया है, क्या उसी आधार पर प्राइमरी और सेकेन्डरी एजूकेशन के लिए भी कोई कमिशन बनाने का विचार रखती है जिसकी वजह से हायर सेकेन्डरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी को स्वयं रोजगार उपलब्ध हो सके? क्या सरकार इस तरह से शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है?

श्री डी० पी० यादव : इस तरह के कमिशन बनाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। हमारे दिल्ली स्थित नेशनल कौंसिल आफ एजूकेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग है और उसकी चार शाखाएं हैं और ये काफी अच्छा काम कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य को इन्हें देखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे वहां चलें और स्वयं इन्हें देखें कि हम इनमें किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर अलग-अलग जगह पर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और उसी के अनुरूप ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी योजना में जो लक्ष्य रखा गया था देश में कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन दी जायेगी, क्या वह लक्ष्य छोड़ दिया गया है? क्योंकि आपने इसमें जो जानकारी दी है उसमें आपने 6 से 14 वर्ष के पूरे ग्रुप के बारे में दी है जिसको की तीसरी योजना में पूरा कर लिया जाना चाहिये था। इस चीज के बारे में आपने कुछ नहीं बतलाया है। आपने इस सम्बन्ध में जो कारण बतलाये हैं, वे कारण वास्तव में उचित मालूम नहीं देते हैं। आपने कहा कि अपर्याप्त दाखिला और प्रारम्भिक शिक्षा में अधिक संख्या में विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ना ये तो उसी तरह का कारण हुआ कि जितने लोग मरे वे इसलिए मरे कि उनकी जान निकल गई थी। मैं यह कोई कारण नहीं समझता हूं। क्या आप बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है या आप इस तरह की कोई जांच करवायेंगे कि जहां पर अपर्याप्त दाखिला हुआ है या बच्चे छोड़कर चले गये, उसका क्या कारण था?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का जवाब मैं पहिले दे चुका हूं, लेकिन मैं पुनः भाई महावीर को याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमने 1960 में टार्गेट पूरा करने की उम्मीद की थी, वह नहीं हो सका। शिक्षा मंत्रालय इस बात को जानता है कि इस बारे में गलती हुई है और इस बात को लेकर हम चलते हैं। लेकिन अधिक गरीबी के कारण भी शिक्षा की प्रगति में रुकावट हुई है। यह तो एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जिसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है।

SHRI JANARDHANA REDDY : Sir, it has been stated that many factors have contributed to 'he increase in the number tes such as the large increase in population, inadequate enrolment of children in the age group of 6-14, etc. May I know from the Government whether they are able to give adequate number of posts to those States which have adequate enrolment? For example, in Andhra Pradesh, I think the number of posts . . .

MR. CHAIRMAN : It is not relevant.

SHRI JANARDHANA REDDY : May I know, Sir, the teacher-student ratio which the Government proposes to maintain?

MR. CHAIRMAN: That is also not relevant,

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, 15-25 वर्ष तक के लोगों की निरक्षरता समाप्त करने की योजना क्या है यह इसमें प्रकट नहीं हुआ है। वैसे आपने कहा है कि हम एक लाख शिक्षक एपौइन्ट करेंगे प्राइमरी स्कूल्स के लिए, लेकिन जो 15-25 वर्ष के लोग निरक्षर हैं उनकी निरक्षरता जल्दी से जल्दी दूर हो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री डी० पी० यादव : 15-25 वर्ष तक के एज ग्रुप को साक्षर बनाने के सम्बन्ध में हमारे केन्द्रीय संगठन और राज्य सरकार के मंत्रियों ने यह अनुभव किया कि ऐसी जगह पर पैसा न लगाया जाय या उसका आबंटन न किया जाय, जो यूजलेस हो। इस ग्रुप पर हमें अपनी शक्ति इन्टेसीफाई करनी चाहिए। प्राइमरी को इन्टेसीफाई कर रहे हैं, आगे आने वाले प्लान में काफी शिक्षक देंगे, लेकिन 15-25 वर्ष तक के जो निरक्षर हैं उन पर डिफरेंट कार्नर से, डिफरेंट एंगिल से अटैक करें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री डी० पी० यादव : उसके लिए हमने अनेक व्यवस्थाएं की हैं—वोकोशनल एजूकेशन है, फंक्शनल लिट्रेसी प्रोग्राम है, श्रमिक विद्यापीठ का प्रोग्राम है, अलग-अलग जगहों में जैसी शिक्षा चाहिए उसी प्रकार से हम लोग देंगे ।

SHRI THILLAI VILLALAN : Eradication of illiteracy is one of the important Constitutional directives. For the fulfil-ni'"r of this objective, I would like to know from the hon. Minister whether this Government is having any special programme for introducing free and compulsory education at primary and elementary levels throughout the country. Of course, education is in the hands of the State Governments. Still I would like to know whether this Government is having any special programme for the current academic year.

SHRI D. P. YADAV : It is a vast problem and unless we expand primary education, we cannot achieve this target and for achieving the target in primary education we have explained many a time the efforts we aie making.

SHRI N. G. GORAY : I would like to know whether instead of making a general Statem nt that the number of illiterates has increased from this to that, will it not he more profitable to identify those areas where illiteracy has grown so that your intensive efforts could he directed to those areas. What I have in mind is your scheme like 'youth against famine'. Is it not possible to identify those areas where illiteracy is growing or is not being dealt with properly? After that, you should direct all your efforts in such manner that those areas get concen trated treatment.

SHRI D. P. YADAV : I woi.ld humbly submit that Shri Goray's suggestion is laudable and our efforts are also in that direction. The greatest problem is the achievement and for that a concerted effort is needed and in this programme voluntary organisations, colleges and other academic institutions—all have to participate.

SHRI SAWAISINGH SISODIA : One of the factors which has contributed to the increase in the number of illiterates is inadequate enrolment of children of the age group from 6 to 14. I would like to know whether the Education Ministry has taken due care to find out who is at fault in this respect and whether the Central Government has given the requisite financial aid to State Governments and the State Governments, even aftei that, were not able to open new schools.

SHRI D. P. YADAV : The action of the Central Government should be catalytic agent and not a direct action.